



ग्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--- सण्ड 3--- जपक्रवड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31]

नई विल्ली, मगलवार, जनवरी 18, 1972/पौष 28, 1893

No 3rl

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 1972/PAUSA 28, 1893

इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलम के कप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January 1972

S.O. 40(E).—Whereas the Central Government has, as required by sub-section (2) of section 78C of the Indian Patents and Designs Act, 1911 (2 of 1911), reconsidered the question whether the direction issued under sub-section (1) of the said section to the Controller by the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Deptt. of Industrial Development) No. S.O. 1631, dated the 22nd April, 1969, as published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii), dated the 3rd May, 1969, read with the notification of that Government in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade No. S O. 235, dated the 20th January, 1970, as published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated the 20th

January, 1970, and the notification of that Government in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S.O. 364, dated the 19th January, 1971, as published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated the 20th January, 1971, continues to be necessary or expedient in the public interest;

And, whereas, on such reconsideration it appears to the Central Government that the said direction continues to be necessary in the public interest;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of the said section, the Central Government hereby notifies that the said direction continues to be necessary in the public interest.

[No. F.31(3)-PP&D/68.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

भौद्योगिक विकास मंत्रालय

म्र धिसूचना

.नई **विल्ली 18 जनवरी, 1972**

का० ग्रा॰ 40(ग). — यतः केन्द्रीय सरकार ने, जैसा की भारतीय पेटन्ट तथा डिजाइन ग्रिधिनियम 1971 (1971 का 2) की धारा 78 ग की उपधारा (2) के अनुसार आवश्यक है, इस प्रश्न पर फिर से विचार किया कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन नियंत्रक के अधीन नियंत्रक को भारत सरकार के भूतपूर्व श्रीधोगिक विकास, श्रांतरितक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (श्रीद्योगिक विकास विभाग) की श्रिधसूचना संख्या का॰ 1631 दिनांक 22 अभ्रेल 1969 हारा जारी किए गये निवेण को जो भारत के राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (2) दिनांक 3 मई, 1969 में प्रकाशित हुआ। सरकार के श्रीद्योगिक विकास तथा श्रांतरिक व्यापार मंत्रालय की श्रिधसूचना संख्या का॰ श्रा॰ 235, दिनांक 20 जनवरी, 1970 जो भारत के श्रसाधारण राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3(2), दिनांक 20 जनवरी, 1970 में प्रकाशित हुई श्रीर उस सरकार के भौद्योगिक विकास तथा श्रांतरिक व्यापार मंत्रालय (श्रीद्योगिक विकास विभाग) की श्रिधसूचना संख्या का॰ श्रा॰ 364, दिनांक 19 जनवरी, 1971 जो भारत के भसाधारण राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3(2), दिनांक 20 जनवरी, 1971 जो भारत के भसाधारण राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3(2), दिनांक 20 जनवरी 1971 में प्रकाशित हुई के साथ पढ़ते हुए, आगे जारी रखना जनहित में भावश्यक अथवा का वित है। श्रीर यतः इस पुनविचार पर केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत हुआ कि अवत निदेश जन हित की दृष्टि से भ्रावश्यक है।

भव, श्रतः, उक्त धारा की उपधारा (3) के श्रनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्दारा भाधसूचित करती है कि उक्त निदेश जनहित मे श्रावण्यक है।

[सः एफ०-31 (3)-पी० पी० एण्ड की०/68] न्नार० के० तलवार, संयुक्त सचिव।